भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1395
दिनांक 01.08.2000 को उत्तर के लिए

हिंदी का प्रचार-प्रसार

1395. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है लेकिन हिंदी, दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाने और हिंदी में पुस्तकों के प्रकाशन पर करोड़ों रूपए जरूर खर्च किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग-वार और वर्षवार हिंदी प्रचार-प्रसार हेतु खर्च कि गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (आई0डी0 स्वामी)

(क), (ख) तथा (घ) जी नहीं । वस्तुस्थिति यह है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग सहित सभी मंत्रालय /विभाग प्रयासरत हैं । इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागयो/कार्यालयों आदि द्वारा हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा आदि आयोजित किए जाते हैं । इस प्रकार के आयोजनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और अन्य प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं । इन आयोजनों पर व्यय की जाने वाली राशि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होती है ।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा वृत्तचित्रों तथा टी0वी0स्पाटस आदि का निर्माण करवाया जाता है । इसके अतिरिक्त, प्रचार सामग्री के रूप में वार्षिक कैलेंडर तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टर आदि भी छपवाए जाते हैं । विभाग द्वारा 'राजभाषा भारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका तथा मासिक पत्र 'राष्ट्रीय राजभाषा समाचार' का भी प्रकाशन किया जाता है । उपर्युक्त सामग्री देशभर में स्थित भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ संस्थानों आदि में वितरित की जाती है । विभाग द्वारा 5 फरवरी, 2000 से 13 फरवरी, 2000 तक आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पहली बार अपना एक स्टाल भी लगाया गया जिससे हिंदी में प्रकाशित स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ ।

(ग) राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते।